दिनांक 29.01.2015 को 3.00 बजे अपराहन में कृषि विभाग, विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य में कृषि ऋण प्रवाह से सम्बन्धित समस्यायें एवं रणनीति तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं सम्बद्ध विषयों की उप समिति की बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. महाप्रबंधक नबार्ड द्वारा बैठक में उपस्थित कृषि उत्पादन आयुक्त/नबार्ड के पदाधिकारीगण/बैंकों के पदाधिकारियों/कृषि विभाग एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधियों का अभिनन्दन किया गया तथा बताया गया कि नबार्ड द्वारा Potential Linked Plans (PLP) तैयार किया जाता है जिसके आधार पर State Credit Seminar का आयोजन किया जाता है तथा Credit Projection पर चर्चा होती है। बिहार राज्य बैंक ऋण के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। राष्ट्रीय औसत (National Average) से पीछे है जिसका C. D. Ratio 40% के करीब है। वित्त पोषण में कुछ परेशानियाँ/समस्यायें हैं जिनका शीघ्र समाधान अत्यावश्यक है।
3. नबार्ड द्वारा Power Point Presentation के द्वारा वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का Sector-wise Potential Linked Plan (PLP) Projection को दर्शाया गया। वर्ष 2015–16 के लिए राज्य में विकास के लिए विभिन्न सेक्टर का अलग–अलग विस्तार से चर्चा की गई।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि राज्य में बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रवाह की स्थिति दिसम्बर 2014 तक बहुत खराब है। इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होने Allocation बढ़ाने या स्वीकृति (Sanction) को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होने बतलाया कि सरकार का कार्य facilitation का है। Credit flow नहीं होने पर Growth संभव नहीं है। उन्होने बतलाया कि पाँच वर्षों का कृषि रोड मैप का लक्ष्य है। योजनाओं में ज्यादा अनुदान राशि देकर कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिस Sector में अनुदान घटाया गया है उसमें वित्त पोषण (financing) की आवश्यकता है। पॉली हाउस के निर्माण में कृषकों को बैंकों से सहयोग की आवश्यकता है।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि राज्य पशुपालन के मामले में पिछड़ रहा है। कोई अनुदान राशि के बिना (beyound subsidy) पशुपालन/मत्स्य पालन में ऋण की स्वीकृति कैसे होगी इसपर ध्यान देने हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया गया। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि पशुपालन अन्तर्गत बीमा नहीं होने से परेशानी होती है। बीमा के क्षेत्र में सहयोग की कहाँ आवश्यकता है इस सम्बन्ध में सूचित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई – एस0 एल0 बी0 सी0)

6. राज्य में Poultry की संख्या बढ़ाने/Floriculture बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं इसके चिन्हित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई – एस0 एल0 बी0 सी0)

7. नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि राज्य में Per Capita आमदनी राष्ट्रीय औसत (National Average) का 1/3 है। प्राइवेट निवेश को राज्य में किस प्रकार बढ़ाया जाय इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है।
8. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि फसल ऋण योजना अन्तर्गत per capita(प्रति किसान क्रेडिट कार्ड) जो ऋण दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है। इसे बढ़ाने की आश्यकता पर बल दिया गया। KCC (No) एवं Quantum (Amount) घट रहे हैं। इसे Identify किया जाय। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा बताया गया कि के0 सी0 सी0 ऋण में अधिकतम एक लाख रूपया तक ऋण लेना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हे जमीन बंधज नहीं करना पड़ता है। राज्य में ऋण की

वसुली कम होने तथा जाली भूधारिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण कम वित्त पोषण बताया गया।

(कार्रवाई – एस0 एल0 बी0 सी0)

9. सहायक महाप्रबंधक, एस0 एल0 बी0 सी0, पटना द्वारा बतलाया गया कि कुल 76.9 लाख KCC में 36 लाख के0 सी0 सी0 के क्रियाशील खाते हैं।

10. कृषि विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि कृषि विभाग द्वारा राशि खर्च कर प्रखंड स्तरीय किसान क्रेडिट कैम्प का आयोजन किया जाता है। कैम्प में प्राप्त आवेदन बैंकों को भेजे जाते हैं। बैंक अधिकांशतः आवेदनों को Entertain किए बिना प्रखंड विकास पदाधिकारी को वापस कर देते हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा के0 सी0 सी0 आवेदन का बैंक द्वारा प्राप्ति रसीद देने तथा इसे Online करने हेतु Centralise Portal बनाने का सुझाव दिया गया।

(कार्रवाई – एस0 एल0 बी0 सी0)

11. कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा एक ही जमीन पर एक से अधिक बैंक शाखाओं से कृषि ऋण लेने की सूचना दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रत्येक किसान जो सरकारी योजना का लाभ उठा रहें हैं को एक Identification No. निगर्त करने का सुझाव दिया गया ताकि इससे duplication की संभावना को समाप्त किया जा सके।

(कार्रवाई – कृषि विभाग/एस0 एल0 बी0 सी0)

12. नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि भूमिहीन/पट्टाधारी/बटाईदार कृषकों के Joint Liability Groups (J.L.G.) को दो तरीके से ऋण स्वीकृत कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्तिगत रूप से (Individually) तथा दुसरा J. L. G. है। JLG में Guarantee सभी लोग मिलकर लेते हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कृषि विभाग की आत्मा योजना के Farmers Interest Group (F.I.G) से J. L. G. को जोड़ने का सुझाव दिया गया।

13. सहायक महाप्रबंधक एस0 एल0 बी0 सी0 संयोजक भारतीय स्टेट बैंक पटना द्वारा जानकारी दी गई कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा J.L.G. को ऋण की स्वीकृति की जा रही है जबकि व्यवसायिक बैंक द्वारा बहुत कम J.L.G. को ऋण की स्वीकृति की गई है। व्यवसायिक बैंकों तथा सरकार के स्तर पर अलग–अलग J. L. G. के वित्त पोषण में बढ़ावा हेतु कार्यक्रम करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई – एस0 एल0 बी0 सी0)

14. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा विभिन्न फसलों के Scale of Finance के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर तकनीकी समिति (State level Technical Committee) का निर्माण करने का निदेश दिया गया। साथ ही अगस्त–नवम्बर माह तक (Scale of Finance) को तैयार कर जिले में भेजने का निदेश दिया गया ताकि इसके आधार पर जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा भी फसलों को Scale of finance निर्धारित किया जा सके।

(कार्रवाई – निदेशक, पी0 पी0 एम0, बिहार)

15. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा राज्य में विभिन्न फसल उत्पादों धान/गेहूँ इत्यादि की अधिप्राप्ति हेतु एक Revolving Fund की आवश्यकता पर बल दिया गया। नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई की छतीसगढ़ राज्य में 2000 करोड़ (दो हजार करोड़) रूपया अधिप्राप्ति के लिए नबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। बिहार राज्य में भी किया जा सकता है।

(कार्रवाई – खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार
महाप्रबंधक, नबार्ड, मौर्यालोक, पटना)

16. सहायक महाप्रबंधक एस0 एल0 बी0 सी0, पटना द्वारा जानकारी दी गई कि कृषि ऋण वितरण में बिहार राज्य सहकारिता बैंक की उपलब्धि एक प्रतिशत से भी कम है। इसे अगले दो वर्षों में 15% से उपर ले जाने तथा कृषकों को Rupay card/ATM कार्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई –उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना)

17. जल संसाधन/लघु जल संसाधन विभाग की नबार्ड से सम्बन्धित योजनाओं पर चर्चा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रधान मंत्री सिंचाई योजना आने के बाद इसमें व्यापक परिवर्तन की संभावना बतलायी गई।

18. पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में Cross-breed Animals की कमी हो रही है तथा Animals Breedig Farms को पुनर्जिवित करने की आवश्यकता है। जानवरों के हाट/मेला सरकार के स्तर से लगाने पर बल दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा गोशाला को आधुनिकीकरण कर Breeding Centre के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया। उन्होने बताया कि राज्य में पावर टीलर का उपयोग हो रहा है तथा बैल खत्म हो रहे हैं। बैल का किस रूप में उपयोग किया जाय यह सोचनीय विषय है। नबार्ड के अधिकारियों द्वारा कम रकबा वाले कृषकों को खेती में पुनः बैल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।

(कार्रवाई – पशुपालन विभाग, बिहार, पटना)

19. मुर्गीपालन से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि बीमा सम्बन्धी कार्य हो जाने के बाबजूद भी मूर्गीपालन फार्म के लिए बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति नहीं किया जा रहा है। उन्होने बिना अनुदान के कलस्टर में विभिन्न क्षेत्रों में ऋण स्वीकृति पर बल दिया।

(कार्रवाई – एस0 एल0 बी0 सी0/पशुपालन विभाग, बिहार)

20. कृषि यांत्रिकरण योजना की समीक्षा के क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा राज्य में कृषि यंत्रों के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर बल दिया गया। उन्होने अनुदान वाले कार्यक्रमों पर उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण द्वारा 52 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 184 करोड़ रूपया अनुदान भुगतान की सूचना दी गई।

(कार्रवाई – संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, बिहार, पटना)

21. नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि कृषि ऋण प्रवाह से सम्बन्धित आंकड़ों के संग्रहण/संकलन में जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसपर कार्य/अध्ययन करने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा मुख्यमंत्री शोध/प्रोत्साहन योजना में उपलब्ध राशि से इस कार्य को करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई – एस0 एल0 बी0 सी0 महाप्रबंधक, नबार्ड, मौर्यालोक, पटना)

22. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना द्वारा गत एस0 एल0 बी0 सी0 की कृषि की उप समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के सम्बन्ध में चर्चा की गई। सहायक महाप्रबंधक, एस0 एल0 बी0 सी0 द्वारा बतलाया गया कि प्रत्येक बुद्धवार को बैंक शाखा के स्तर पर किसान क्रेडिट कैम्प का आयोजन किया जाना था परन्तु इस सम्बन्ध में बैंकों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उन्होने एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया। वर्ष 2010–11 में फसल बीमा की लम्बित राशि कृषकों को भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग को पत्र निर्गत करने की जानकारी कृषि विभाग के पदाधिकारी द्वारा दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव से भी वार्ता करने का आश्वासन दिया गया।

23. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि राज्य में कुछ युवा लोग जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं Egg Laying Birds परियोजना के अन्तर्गत अंडे का उत्पादन करना चाहते हैं। राज्य में प्रतिदिन 80 लाख अंडे की खपत है तथा यह दूसरे राज्य आन्ध्र प्रदेश/तमिलनाडु इत्यादि से आपूर्ति की जाती है। राज्य में अंडे का उत्पादन होने पर कम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। इस संबंध में सिवान जिला में काफी अधिक आवेदन बैंकों में लंबित है। उन्होने उपस्थित बैंक अधिकारियों से राज्य में अंडा उत्पादन संबंधी योजना में ऋण स्वीकृति हेतु अनुरोध किया।

(कार्रवाई – एस0 एल0 बी0 सी0)

24. नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा कृषि एवं अन्य Allied activity (Dairy, Fishery, Poultry) के विभिन्न योजना अन्तर्गत दिशा निर्देश/मार्गदर्शिका की प्रति विभागीय website पर डालने का अनुरोध किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा इसे विभागीय वेबसाईट पर डालने के साथ योजना से सम्बन्धित लिफलेट/पम्पलेट इत्यादि की प्रति किसान क्लब/बैंक एवं अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई – पशु एवं मत्स्य पालन विभाग,
निदेशक, पी0 पी0 एम0, बिहार, पटना,
निदेशक, उद्यान बिहार, पटना,
निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना)

25. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि विभिन्न योजना अन्तर्गत अनुदान की राशि अलग–अलग बैंकों में रखने में परेशानी होती है। एक ही बैंक में अनुदान की राशि को रखने तथा उक्त बैंक द्वारा अनुदान राशि को अन्य बैंकों को विमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में सहायक महाप्रबंधक, एस0 एल0 बी0 सी0 से सुझाव की मांग की गई।

(कार्रवाई – एस0 एल0 बी0 सी0)

अन्त में नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(विजय प्रकाश)
कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक : 783 दिनांक : 10-02-15

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला डाक बंगला रोड, पटना/सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पाँचवां तल्ला, प० गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक : 783 दिनांक : 10-02-15

प्रतिलिपि : निदेशक, पशुपाल विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, डेयरी, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्यपालन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/उप महाप्रबंधक, कम्फेड, बिहार, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इंडिया लि०, गैण्ड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना/उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारिता बैक, पटना/सयुंक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण–सह–प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण योजना, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, शिक्षा, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/उप कृषि निदेशक, सूचना, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक, सांख्यिकी–सह–प्रभारी पदा०, विपणन कोषांग/सिचाई विशेषज्ञ, पी0पी0एम0 कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक : 783 दिनांक : 10-02-15

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9.2.15

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।